

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-२

देहरादून: दिनांक: १५ नवम्बर, 2006

विषय: वित्तीय वर्ष 2006-07 में राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत जनपद चम्पावत की कांडा-श्यामाताल पम्पिंग पेयजल योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3403/अप्रैजल-चम्पावत/दिनांक 13.09.2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत जनपद चम्पावत की कांडा-श्यामाताल पम्पिंग पेयजल योजना अनु०लागत रु० 149.63 लाख के प्राक्कलन पर टी०ए०सी० के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई अनु०लागत रु० 122.40 लाख (रु एक करोड़ बाईस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि के प्राक्कलन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में रु० 50.00 लाख (रुपये पचास लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में दो बाराबर किश्तों में पूर्व किश्त का पूर्ण उपयोग के बाद ही दूसरी किश्त आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2007 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय। अवमुक्त की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के पश्चात उपरोक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

- 2-उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में अनुदान सं०-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति- आयोजनागत -102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-03-ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर - 00 -20- सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे" डाला जायेगा ।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं०- 1054/XXVII(2)/2006 दिनांक 02 नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)

अपर सचिव

पृ० सं० 2024/उन्तीस(2)/06-2(97पे०)/2006 तददिनांक

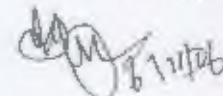
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2. मण्डलायुक्त कुमायूँ मण्डल ।
3. जिलाधिकारी, देहरादून ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान ।
6. वित्त अनुभाग-2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तरांचल ।
7. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तरांचल ।
8. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ ।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून ।
- ✓ 10. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून ।
11. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)

उप सचिव



4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 5-कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
- 6- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार संक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।
- 7- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार संक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 8- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताये तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 9- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
- 10- आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- 11- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
- 12- यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हों, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।
- 13- जी०पी०डब्ल्यू० फार्म ९ की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्यों को पूर्ण न करने पर 10प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत से निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
- 14- मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।
- 15- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

२/